RESEARCH PAPER | Sociology | Volume : 3 | Issue : 1 | January 2013 | ISSN - 2249-555X



Arthik Vikas ke Nidarshak

KEYWORDS

Godalka Anita P

Prof. Dept. Of Sociology, Government Arts College, Ranavav, Porbandar

ABSTRACT विश्व आर्थिक रूप से दो हिस्सो में विभाजित है । एक ओर समृ विकसित देश तो दूसरी ओर भूखमरे की स्थिति में रहे अल्प विकसित देश । इतना ही नही समृ और गरीब देशों के बीच अंतर बढता गया है । गरीबी और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आप में वृद्धि करके प्रजा के जीवन स्तर में सुधार करना चाहिये । इस के लिये इन देशो को आर्थिक विकास करना चाहिए । अल्पविकसित देशों की आर्थिक विकास की माँग वास्तव में आर्थिक समानता और न्याय की माँग है । अल्प विकसित देशों के इन प्रयासो के लिए प्रगति, वृद्धि और विकास जैसे अलग – अलग आर्थिक विकास के निर्देशक रहे है । यह देखने और समजने के लिए प्रस्तुत अभ्यास किया गया है ।

आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की व्याख्याओं से हमने देखा कि वास्तविक राषट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है, लेकिन आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धिसे कुछ विशेष है । विकास मेंआर्थिक वृद्धि तो है ही, इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आय का समान वितरण, विकास के मौके, व्यक्ति स्वातंत्य जैसे बहुत से बिनआर्थिक बातों पर आधारित मुदे भी है । जो कीलोगों की सोच में परिवर्तन, उत्पादन साधनों की गतिशीलता, मनोवैज्ञानिक और संस्थाकीय अभिगमों में परिवर्तन आदि है । इस प्रकार आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं यह तो प्रतिव्यक्ति आय अथवा राष्टिय उत्पादन में आ रहे परिवर्तनों से मापा जा सकता है, लेकिन आर्थिक विकास, जैसे पर कहा गया है कि बहुत सी नहीं मापी जा सकने वाली बातों को भी अपने में समाविष्ट करता है, मापना मुश्किल है।

दूसरा, आर्थिक वृद्धि मुख्यत: विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ खयाल (concept) है जहाँ पर लोग उत्पादन, आय, खर्च के हिसाब व्यवस्थित रूप से रखने की आदत और तकनिक रखते है । इसलिए आर्थिक वृद्धि आसानि से मापी जा सकती है । लेकिन अल्प विकसित या विकासशील देशों में विकास की प्राथमिक अवस्था में अशिक्षा, गैरजिम्मेदार बर्ताव और माहिती प्राप्ति के योग्य साधनों के अभाव में विकास के सही आंकड़े नहीं मिल पाते । इस समस्या को हल करने के लिये अर्थशास्त्रीयों और अलग अलग आंतरराष्टीय संस्थाओं ने आर्थिक विकास को मापनेके एक से अधिक मापदंड तैयार किये है । इन निर्देशकों में भी बदलते संजोगों के साथ बदलाव आया है ।कोई भी मापदंड या निर्देशकों मेंभी बदलते संजोगों के साथ बदलाव आया है । काई भी मापदंड या निर्देशक पूर्णत: माहितीप्रद नहीं है । क्यूँकि अर्थतंत्र के अल्पविकसित होने के कारण भी अलग अलग है, उन सब में आर्थिक विकास मापने के मापदंड भी अलग अलग है । इस प्रकार आर्थिक विकास मापने के लिये एक से अधिक मापदंडो को लिया जाता है ।

❖ आर्थिक विकास के निर्देशक मापदंड :
- रा✓ट्रीय आय
- प्रतिव्यक्ति आय
- जीवन की लघुतम आव★यक्ताएँ
- जीवन की भौतिक गुणवताओं का अंक
- आर्थिक कामगीरी का अंक
- अन्य

❖ राष्ट्रीय आय :
आर्थिक विकास मापने के लिये ोारू में सकल राष्ट ीय उत्पाद को अधिक उपयोग में लिया जाताथा । १९५० से १९७० के समय में ऐसी मान्यता थी कि राष्ट ीय वास्तविक आय व राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होने से आर्थिक विकास होगा और बेरोजगारी का प्रश्न अपने आप हल हो जायेगा ।

इस विचार के अनुसार किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार आर्थिक विकास पर है । UNO के विशेषज्ञ और कई अर्थशास्त्रीयों ने विकसित और अल्पविकसित देशों के बीच का तफावत राष्ट्रीय आय के स्तर पर बताया है । आम तौर पर जैसे जैसे आर्थिक विकास ज़्यादा हो वैसे वैसेदेश की राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय ज़्यादा देखने मिलती है । राष्ट्रीय उत्पादन के अभिगमों की चर्चा दोसंदर्भों की चर्चा दो संदर्भों में की गई है, १ वास्तविक राष्ट्रीय आय, २ वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय ।

निम्न लिखित तीन कारणों से इन मापदंडो का स्वीकार किया गया है :
१ उस समय ऐसी मान्यता थी कि देश में विकास होने से बाजार के परिबलों के द्वारा उसका लाभ अपने आप ही गरीबों तक पहुँचेगा ।
२ अगर बाजार के परिबल धनिकों को अधिक धनिक बनाकर विकास के फल मर्यादित लोगों के हाथ में केन्द्रित करेंगे तो लोकतांत्रिक और गरिबों की चिंता करने वाली सरकार प्रगतिशील कर व्यवस्था और कल्याणलक्षी सार्वजनिक खर्च की नीति के द्व ारा विकास के फल गरीबों तक पहुँचायेगी ।
३ उस समय ऐसी मान्यता थी कि आर्थिक विकास के शूरू के चरण में मुख्य समस्या पूंजी निर्माण करके आर्थिक विकास का ढाँचा (infrastructure) तैयार करने की है । इस प्रकिया के दौरान आय की असमानता या गरीबी का प्रश्न उपस्थित होता है तो वह अल्पकालिन होगा और उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ।

❖ प्रतिव्यक्ति आय :
प्राण आर्थर लेक्सि और जेकोब वाइनर के अनुसार अगर देश की प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में लंबे समय अवधि के दौरान सतत वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास हो रहा है ऐसा कह सकते है । इसलिये प्रतिव्यक्ति आय में हो रही वृद्धि आर्थिक विकास का निर्देशक है । प्रतिव्यक्ति आय को विकासके निर्देशक के रूप में ध्यान में लेते समय निम्न लिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

- राष्ट्रीय आय की तरह प्रतिव्यक्ति आय भी बाज़ार किंमतों पर और स्थिर किंमतों पर गिनती की जाती है । उदाहरण के रूप में १९७८–७९ में भारत की प्रतिव्यक्ति आय ६३३ रू. थी । जो बाजार किंमतों पर १२५० रू. थी और स्थिर भावों पर ७१२ रू. थी । इस प्रकार प्रतिव्यक्ति आय की गिनती करते समय भी किंमतों में वृद्धि दर को ध्यान में लेकर किंमत वृद्धि दर काटकर शुद्ध प्रतिव्यक्ति आय को ही ध्यान में लेना चाहिये और स्थिर किंमतों पर प्रतिव्यक्ति आय मापनी चाहिये ।
- विभिन्न देशों की तुलना प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर करते समय उन देशों की मुद्रा को आंतरराष्ट्रीय मुद्रा अधिकतर अमेरिकन डोलर में परिवर्तित करनी होती है । लेकिन सभी देशो में विदेशी मुद्रा के उपर अंकुश लगे हुए होने से सही मूल्य नहीं जाना जा सकता । इसलिये यह मापदंड विकास की कक्षा की तुलना करने में उपयोगी नहीं रहता ।
- देश की कुल राष्ट्रीय आय की जनसंख्या से विभाजीत करने से जो जवाब मिलता है वह प्रतिव्यक्ति आय प्रजा के जीवन स्तर को स्पर्श करता है । इसलिये विकास के राष्ट्रीय आय की तुलना में यह प्रतिव्यक्ति आय का मापदंड बेहतर है ।
- प्रतिव्यक्ति आय में बरसों तक लगातार वृद्धि होनी चाहिये । एक वर्ष अच्छी बारिश से खेती औरऔधोगिक उत्पादन में वृद्धि हो और परिणाम स्वरूप प्रतिव्यक्ति आय बढ़ें और दूसरे वर्षहड़ताल, बिजली की कटौती, कम बारिश, कच्चे माल की कमी आदि कारणों से औधोगिक औरखेत उत्पादन में कमी होने से प्रतिव्यक्ति आय कम हो ता वह आर्थिक विकास नहीं कहा जायेगा। यह स्थिति विकासशील अर्थतंत्र में देखने मिलती है । अगर अर्थतंत्र में बेहतर पूंजी साधनों काप्रमाण बढ़े और टेकनोलोजीकल परिवर्तन होने से उत्पादन में लगातार वृद्धि होने से लंबे समय तक प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती रहे वह आर्थिक विकास है ।
- विकास प्रतिव्यक्ति उत्पादनक्षमता में हो रहे परिवर्तन बताता है । जिस देश में वहाँ की जन संख्या वृद्धि दर से ँचे दर से वस्तुएँ और सेवाओं का उत्पादन होता है उस देश की उत्पादन क्षमता आश्रर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ रही है, इसलिये ऐसा कह सकते है कि प्रतिव्यक्ति आय विकास को जानने के लिये आदर्श निर्देशक है ।

❖ जीवन की लघुतम आव★यकताएँ :
१९५० से १९७० के दशक के दोरान एक ऐसी दृढ मान्यता थी कि राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होने से अपने आप आर्थिक विकास होगा और गरीबी तथा बेरोज़ गारी की समस्या दूर होगी । होलीस चेनरी के अनुसार १९५० से १९७० के समय के दौरान विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में १५० से २०० टका जितनी वृद्धि हुई फिर भी आय की असमानता बढ़ी और गरीबी का प्रमाण कम नहीं हुआ । इस बात को ध्यान में रखकर प्रा महेबूब – उल हक्क जैसे अर्थशास्त्री विकास के निर्देशकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये ह। उनके मतानुसार देश की राष्ट्रीय आय या प्रतिव्यक्ति आय कितनी है यह बात नहि लेकिन समाज के गरीब लोगों के जीवन की गुणवता में सुधार हुआ है या नहीं इस बात को आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में लेनी चाहिये । प्रा लिप्सी और लेबेव्स्टाईन के मत अनुसार अगर समाज के गरीब लोगों को मिलने वाली आव★यक वस्तुएँ और मूलभूत ढाँचेगत सुविध ाओं का प्रमाण बढ़ता है तो आर्थिक विकास हो रहा है ऐसा हम कह सकते है ।

गरीब लोगों के जीवन की गुणवता तभी सुधर सकती है जब गरीबी, भूखमरे की स्थिति, निरक्षरता, रोगों का प्रमाण, अकाल मृत्यु, कम आयुष्य जैसे सामाजिक और आर्थिक प्र★न सुल ो । ये प्र★न तभी सुलजा सकते है कि जब गरीबों को प्रमाण और गुणवता की दृष्टि से योग्य मात्रा में खुराक, पीने का साफ पानी, वस्त्र, रहने लायक स्वच्छ मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, ईंधन, बिजली आदि प्राप्त हो । याने कि इस वर्ग के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो । दूसरे शब्दों में कहें तो आय का वितरण गरीबों केपक्ष में करने की व्यूहरचना अपनाकर गरीबों को गरीबी की रेखाके नीचे से गरीबी की रेखा के परले जाना चाहिये, जिस से गरीबी का प्र★न दूर किया जा सके ।इस विचार के विरोध में दो

Volume : 3 | Issue : 1 | January 2013 | ISSN - 2249-555X

मुद्दे ठाये गये है । एक, गरीबों की मूलभूत आव★यक्ताएँ संतुष्ट करने के लिये उनके पक्ष में साधनों की फेरबदल करने से अर्थतंत्र की बचत और निवेश कम होंगे, जो लंबे समय की दृष्टि से नुकसानकारी होगा । यह तर्क वास्तविक नहीं है । क्यूँ कि समाज के सभी वर्गों के अनाव★यक खर्च कम करके ये साधन आव★यक्ता संतुष्ट करने के लिये उपयोग मेंलेने हैं । इसलिये बचतों में कभी होना या नई बचतों का सर्जन करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

उसी प्रकार, अमीर लोग ही बचत करते है ऐसी मान्यता पर यह तर्क दिया जाता है, लेकिन वास्तव में विकासशील देशों के अमीर प्रदर्शन प्रभावों ;कमउवदेजतंजपवद ममिबजेद्ध तले उपभोग अधिक करते है ।

❖ जीवन की भौतिक गुणवताओं का आंक :
यु एस् ए की एक निजी संस्था ने उपर के सभी निर्देशको से बेहतर ऐसा जीवन की गुणवताओं का आंक तैयार किया है । इस आंक में अपेक्षित आयुष्य, बालमृत्यु दर और शिक्षा का प्रमाण- इन तीन बातों को ध्यान में लिया गया है । यह आंक ;प्दकमगद्ध तैयार करने के पीछे का उद्देश यह है कि समाज के दुर्लभ वर्ग की मूलभूत आव★यक्ताओं को संतुष्ट किया जाये तो उनके जीवन स्तर अथवा कल्यान में सुधार होता है । ऐसी प्रजा की अपेक्षित आयु बढ़ती है । शिशुमृत्यु की दर कम होती है और शिक्षा का प्रमाण भी बढ़ता है । जनता हंमेशा लंबी और तंदुरस्त आयु जीने की ईच्छा रखती है । उसी प्रकार इस आयु के दौरान उँची शिक्षा और तालीम पाकर समाज में प्राप्त आर्थिक, सामाजिक और राजकीय हक्को को जलदी से पाकर प्रगति की जा सकती है । इसलीये चेलेपबंस फनंसपजल वि स्पिमि प्दकमग आर्थिक विकास का महत्व का निर्देशक है ।

च्फस्प् की रचना इस प्रकार की जाती है । किसी खास वर्ष को आधार वर्ष के रूप में पसंद किया जाता है, उस वर्ष में सभी देशो में अपेक्षित आयु, बाजमृत्यु का प्रमाण और शिक्षा का प्रमाण कितना है इसके आंकड़े इकट्ठे किये जाते है । जिस देश में इन क्षेत्रों में कामगीरी सब से अच्छी हो उस देश के लिये च्फस्प्१०० : माना जाता है । उदाहरण के रूप में १९६० में स्वीडन में दुनिया में सब से अधिक अपेक्षित आयु ७३ वर्ष है । इसलिये ७३ वर्ष को १०० का आंकदिया जाता है । दूसरी औरउसी वर्ष अंगोला में अपेक्षित आयु ३३ वर्ष है, जो वि★व में सब से कमहै । इसलिये ३३ वर्ष को । आंक दिया जाता है । ३३ और ७३ के बीच में अपेक्षित आयु वाले देशों को प्रमाण अनुसार आंक दिया जाता है । इस प्रकार १९६० के वर्ष में स्वीडन में ० से १ वर्ष के बच्चों में मृत्यु का प्रमाण १७ था, जो वि★व में सब से कम है इसलिये १७ को १०० आंक दिये जाते है । उसी वर्ष अपरवोल्टा में सब से अधिक मृत्यु दर बच्चों की २६३ थी इसलिये १०० को १०० अंक मिलते है । उसी वर्ष नाईजर में १ टका आबादी शिक्षित थी इसलिये । को लघुतम अंक। मिलता है । स्वीडन में तीनों बातों के अंक १०० है । इसलिये तीनों का औसत अथवा च्फस्प्१०० : आता है । जीस देश का इस अंक से कम हो उसका आर्थिक विकास कम माना जाती है ।

समय गुज़रने पर जिस देश का बढ़ता जाये उस देश का च्फस्प् विकास हो रहा है ऐसा कह सकते है । उदाहरण के रूप में भारत का १९६० में २८ था जो १९८० में ४२ हुआ, इस प्रकार च्फस्प् बढ़ा है, तो भारत में आर्थिक विकास हो रहा है ऐसा हम कह सकते है । जिस विकासशील देश कच्फस्प्में तेजी से वृद्धि हो उस देश का आर्थिक विकास तेज़ है ऐसा कह सकते है । इस आंक के आधार पर अन्यएक बात का भी पता चलता है, कि यु एस् ए की प्रतिव्यक्ति आय स्वीडन की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में अधिक है इसलिये ऐसा प्रभाव पड़ता है कि स्वीडनका आर्थिक विकास यु. एस ए के आर्थिकविकास की तुलना में कम है । लेकिन १९७० से १९७१ के समय में अमेरिका का च्फस्प्९६ है, जब कि स्वीडन का १०० है । इसलिये अमेरिका की तुलना में स्वीडन का आर्थिक विकास अधिक हुआ है ऐसा हम कह सकते है । उसी प्रकार श्रीलंका की प्रतिव्यक्ति आय १३० डोलर होते हुए भी उसका च्फस्प्कई धनिक देशों की तुलना में अधिक है ।

❖ जीवन की भौतिक गुणवताओं का आंक :
हाल ही के वर्षो में आर्थिक कामगीरी का सर्वग्राही मूल्यांकन करने के लिये आर्थिक कामगीरी का आंक तैयार किया जाता है । जिस में आर्थिक वृद्धि के दर को अधिक महत्व दिया गया है और बेरोजगारी और मुद्राप्रसार के मूल्यों को नकारात्मक मूल्य दिया गया है ।

आर्थिक कामगीरी = वास्तविक आर्थिक वृद्धि का दर / बेरोजगारी का दर मुद्रा+स्फीति का दर

❖ मानव विकास सूचक आंक :
युनाईटेड नेशन्स डेवलोपमेन्ट प्रोग्राम ;न्छक्च्द्ध के द्वारा १९९० में एक नया सूचक आंक प्रस्तुत किया गया, जिसे मानव विकास सूचक आंक ;भ्नउंद क्मअमसवचउमदज प्द् कमगद्ध के नाम से जाना जाता है । यह निर्देशक राष्ट्रीय संपति को मापदंड के रूप में नहीं लेता, बल्कि जीवन काल ;सपमि चंदद्ध साक्षरता एवम् आधाररूप खरीद शक्ति को लेता है । जीवन काल को मापने के लिये जन्म के समय अपेक्षित आयु ध्यान में ली जाती है ।

खरीदशक्ति के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन
आंतर राष्ट्रीय मुद्राकोष ;प्डथ्द्ध में सभी देशों की ळक्च् उसी देश की खरीद शक्ति के आध ार पर मापी है, न कि आंतर राष्ट्रीय विनिमय दर के आधार पर । परिणाम स्वरूप १९९० में भारत की ळक्च् + १००० इपससपवद अंदाज़ी गई थी जो की आंतर राष्ट ीय विनिमय दर के आधार पर मापी गई २९० डोलर से अधिक है । इसी प्रकार भारत की प्रति व्यक्ति आय भी ११५० डोलर मिली जो ३३० डोलर से अधिक है । की इस पद्धति से भारत कि स्थिति वि★व में सब से विकसित अर्थतंत्रों में छठवें स्थान पर आई है ।

❖ अन्य :
आर्थिक विकास देश में उत्पादन पद्धति में हो रहा परिवर्तन, क्षेत्रीय उत्पादन एवम् क्षेत्रीय श्रम आबंटन तथा मांग में हो रहे परीमाणात्मक और गुणात्मक निर्देशको के आधार पर विकास की कक्षा का पता लगाया जा सकता है ।

न्यूज़ीलेन्ड जीम जीम उपदपेजतल वि क्मअमसवचउमदजए ज्तमेंनतल दक कैजंजपेजपबे की ने संयुक्त रूप में आर्थिक विकास के निर्देशक २००५, २००७ आदि में प्रकाशित किये है । विकास के ये निर्देशक सामाजिक निर्देशक और आर्थिक निर्देशक जैसे दो ीमंकपदहे के अंतर्गत विभाजीत किये गये है । सामाजिक निर्देशकों में जनसंख्या का प्रमाण, जनसंख्या विकास दर और ढाँचा, जनसंख्या वृद्धि के निर्णायक, श्रमबल, शिक्षण और साक्षरता, प्राकृतिक संसाधन, आय और गरीबी, खूराक, आवास, ईंधन, ऊर्जा, यातायात आदि पर खर्च का प्रमाण, स्वास्थ्य और शिक्षापर निवेश वगैरह ।

आर्थिक निर्देशकों को मुख्यतः चार विस्तृत क्षेत्रों में बाँटा गया है,
- परिणाम दर्शक निर्देशक
- भौतिक जीवन स्तर के घटक
- वृद्धि और उत्पादक्ता के वाहक के मध्यवर्ती निर्देशक
- आधाररूप निर्देशक

❖ समीक्षा :
समग्र चर्चा के अंत में कह सकते है कि आर्थिक विकास की कुल राष्ट ीय उत्पाद औरप्रतिव्यक्ति आय के मापदंड की तुलना में निर्देशक जीवन की भौतिक गुणवताओं का आंक अधिक अच्छा मापदंड है । प्रा मेयर ने सही कहा है कि विकास के कुल प्रतिव्यक्ति निर्देशांक के प्रतिध्यान देने के बदले वि★व के गरीब देशों में बसने वाले सब से अधिक गरीब लोगों के समूह पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छा जीवन जीने की शर्तें, अच्छा रोज़गार जैसे ध्येय सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिये । विकास ध्येय नहीं लेकिन साध न है । उसके द्वारा गरीबी, असमानता के प्रश्नों का हल ढूँढने के प्रयत्न करने चाहिये ।

फिर भी सभी मापदंड एकदूसरे के साथ जूड़े हुए है । क्यूँकि जीवन की गुणवता सुधारने के लियेप्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि अनिवार्य है । ओर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय आय की वृद्धि अनिवार्य है । इसलिये राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय के निर्देशक आधार रूप निर्देशक है ।

REFERENCE कुमार अेच् डी् , ''जनरल इकोलोजी'', विकास पब्लिशर्स हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, १९९५् द्य क्र राओ अेस् आर् के् , ''इकोनोमीक्स फोर सिविल सर्विसींग'', कोस्मोस बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, १९९५् द्य हेमीक्षा राव – ''विकास का समाजशास्त्र''